राज्यपाल श्री राम नरेश यादव का 64 वें गणतंत्र दिवस समारोह

प्रदेश की जनता के नाम संदेश

प्रिय बहनो और भाईयों,

भारतीय गणतंत्र आज एक वर्ष और परिपक्व हो गया है। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर, विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के नागरिक होने के नाते, मेरी ओर से आप सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आईये, आज हम सब मिलकर देश को आजादी दिलाने वाले अमर शहीदों का पुण्यस्मरण करें और देश के नव-निर्माण के लिये एक जुट होकर आगे बढ़ें।

मैं आज उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्रणाम करता हूं, जिनके त्याग और बलिदान की वजह से हमें आजादी मिली और स्वतंत्र, संप्रभुता सम्पन्न गणराज्य का गठन हुआ। मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा संविधान जहां हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है वहीं उसने हमारे कर्तव्यों को भी रेखांकित किया है। आज जरूरत यह है कि अपने कर्तव्यों और देश के प्रति दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रतिबद्ध हों।

गणतंत्र की सार्थकता तभी है जब जनता को शासन के निर्णयों, कार्यक्रमों और योजनाओं के निर्माण में भागीदार बनाया जाए। इस उद्देश्य को मूर्त रूप देने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों से सीधे संवाद के लिए अब तक 25 पंचायतें आयोजित की जा चुकी हैं जिनमें समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं पर सीधे चर्चा कर उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण फैसले लिये गये हैं। इस वर्ष विद्यार्थियों, फेरीवालों, मछुआरों, वृद्धजनों, वकीलों और हाल ही में युवाओं की पंचायतें सम्पन्न हुई हैं।

मध्यप्रदेश में सामाजिक और भौतिक अधोसंरचना के विकास पर पिछले वर्षों में हुए निरंतर विकास के परिणाम सामने आने लगे हैं। कई स्वतंत्र समीक्षकों ने मध्यप्रदेश का चयन बड़े राज्यों में तेजी से उभरते हुए राज्यों की श्रेणी में किया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदेश की विकास दर का औसत 10.2 प्रतिशत रहा जबकि राष्ट्रीय विकास दर 7.9 प्रतिशत रही। पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदेश की कृषि विकास की दर 18.91 प्रतिशत रही जो देशभर में सर्वाधिक है। माननीय राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में अन्न उत्पादन के मामले में मध्यप्रदेश को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए भारत सरकार के कृषि कर्मण अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है।

इस पुरस्कार का कारण शासन द्वारा लिये गये बहुत से नीतिगत निर्णय भी हैं और हमारे किसानों का परिश्रम भी। हमारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने खेती में नवचैतन्य का संचार किया है। किसानों को अब सहकारी कृषि ऋण जीरो प्रतिशत की ब्याज दर से मिल रहा है। करीब 35 लाख किसानों को 12 हजार करोड़ रूपये के अल्पकालीन कृषि ऋण मुहैया कराया जाना संभावित है। प्रदेश में 75 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिये गये हैं। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जहां बीज की उपलब्धता बढ़ाने के लिये बीज उत्पादक सहकारी समितियां गठित की गई हैं। अब तक दो हजार 48 समितियां गठित की जा चुकी हैं। प्रदेश में गेहूं उपार्जन के लिए ई-उपार्जन योजना प्रारंभ हुई। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश ने 85 लाख मीट्रिक टन गेहूं का रिकार्ड उपार्जन किया। गेहूं और धान के उपार्जन और भण्डारण के हमारे प्रयासों की यूनिक आइडेन्टिफिकेशन अथारिटी ऑफ इंडिया और भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रशंसा हुई है। हमने किसान के खाते में सीधे कैश ट्रांसफर करने की व्यवस्था की है। हमने वेयर हाऊसिंग और लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई है। गांवों में गैर कृषि प्रयोजनों के लिए 24 घंटे बिजली और खेती को 8 घंटे बिजली देने हेतु अटल ज्योति अभियान आरंभ किया गया है।

बुजुर्गों को तीर्थ-यात्रा के लिए "मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना' लागू की गई है योजना के तहत शासन के व्यय पर बुजुर्गों को तीर्थ- यात्रा कराई जा रही है। अभी तक विभिन्न धर्मस्थलों को रवाना हुई ट्रेनों में 32 हजार से भी अधिक यात्री तीर्थों के लिए गये हैं।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अब 16 विभागों की 52 सेवाएं नागरिकों को तय समय-सीमा में प्राप्त होती हैं। अब तक एक करोड़ 57 लाख लोगों ने इस सेवा का लाभ उठाया है। सुशासन के लिए प्रदेश के इस मजबूत और सक्षम कदम को विश्व के सबसे प्रतिष्ठित यू.एन. पब्लिक सर्विस अवार्ड-2012 से पुरस्कृत किया गया है। देश के अनेक राज्यों ने मध्यप्रदेश की इस पहल को अपनाया है।

यह वर्ष प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शानदार उपलब्धियों से भरपूर रहा। इंदौर में 150 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित क्रिस्टल आई.टी. पार्क का लोकार्पण और ग्वालियर में आई.टी. पार्क का भी शुभारंभ हुआ। भोपाल में स्टेट डाटा सेन्टर ने काम करना शुरू कर दिया है। इंदौर में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आई.टी. के 3 हजार करोड़ रूपये के 47 करारनामों पर दस्तखत किए गए। प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार अब विकास खण्ड स्तर तक हो गया है।

देश के पहले गौ-अभ्यारण का प्रदेश के शाजापुर जिले के सुसनेर में भूमि-पूजन किया गया। प्रदेश का दुग्ध-उत्पादन भी राष्ट्रीय दर से लगभग दुगुना हुआ। प्रदेश की मछली उत्पादकता, राष्ट्रीय उत्पादकता 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से दुगुनी 25 किलोग्राम हुई है।

प्रदेश अपना वन क्षेत्र बरकार रखने में सफल हुआ है। प्रदेश को हरियाली और पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में उल्लेखनीय कार्य के लिए युनाईटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एवं द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा ग्रीन ग्लोब फाउन्डेशन अवार्ड मिला है। इस वर्ष तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक प्रति मानक बोरा 650 रूपये से बढ़ाकर 750 रूपये किया गया है। वनवासियों को चिरौंजी, शहद, माहुल पत्ता, आंवला और औषधीय पौधों जैसी वनोपज का नि:शुल्क संग्रहण करने की छूट दी गई है। संग्रहित लघु-वनोपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए हर्रा, महुआ फूल, महुआ गुठली, नीम बीज, करंज बीज, लाख और अचार गुठली का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। वन अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश में पट्टा वितरण कार्य की प्रशंसा राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई है। प्रदेश के ईको टूरिज्म बोर्ड को उच्च गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आई.एस.ओ. अवार्ड मिला है। माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में चार राष्ट्रीय पुरस्कार दिये गये हैं।

प्रदेश में अधोसंरचना विकास के महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। लगभग 90 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण / सुधार हुआ है। पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप की मदद से 30 हजार करोड़ रुपयों की परियोजनाओं पर काम जारी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इस वर्ष में अब तक 334 करोड़ 20 लाख रूपये लागत से 1325 किलोमीटर लम्बी 422 नई सड़कों का निर्माण हुआ है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अब तक 1943 किलोमीटर लम्बी 1015 सड़कों और 7302 पुल पुलियों का निर्माण भी हुआ है। इस वर्ष गांवों में लागू की गई “पंचपरमेश्वर योजना” के अंतर्गत सभी 23008 ग्राम पंचायत को सी.सी.रोड निर्माण और स्वच्छता तथा पर्यावरण विकास के कार्यों के लिये जनसंख्या के मान से धन राशि दी जा रही है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सार्वजनिक उपयोग की स्थाई परिसम्पत्तियों के निर्माण में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी राज्य रहा है। प्रदेश में इस वर्ष में 24 लाख 16 हजार जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को 732 लाख मानव दिवस का रोजगार मुहैया कराया गया है।

महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा के लिये मर्यादा अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के पहले चरण में 12331 ग्रामों को खुले में शौच की बुराई से मुक्त किया गया है।

निर्मल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक करीब 3 लाख घरेलू शौचालयों का निर्माण हो चुका है। राष्ट्रपति ने प्रदेश की 212 ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया है। जल स्वच्छता के नवाचारों के लिए प्रदेश को संयुक्त राष्ट्र रियो पृथ्वी- सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।

महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में प्रदेश में हुए कार्यों की विश्व स्तर पर सराहना हुई है। हाल ही में प्रदेश में महिलाओं के लिए सिविल सेवा में आवेदन की आयु बढ़ाकर 45 वर्ष की गई है। प्रदेश में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने और लिंगानुपात को सुधारने के लिए - "बेटी बचाओ अभियान' एक वर्ष से अधिक समय से संचालित किया जा रहा है। मैं आव्हान करता हूं कि समाज में महिलाओं को समान अधिकार और न्याय दिलाने के लिए हम सब कमर कस लें और व्यक्तिगत स्तर पर भी बेटा-बेटी में भेदभाव न करें। लाड़ली लक्ष्मी योजना में अब तक 13 लाख बालिकाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। योजना की लाभान्वित बालिकाओं के माता-पिता का राज्य शासन द्वारा बीमा कराये जाने का भी निर्णय लिया गया है। प्रदेश के 15 जिलों में लागू सबला योजना के तहत 11 से 18 वर्ष आयु की 17 लाख 33 हजार बालिकाओं को पोषण, स्वास्थ्य स्तर में सुधार और कौशल उन्नयन द्वारा सशक्त किया जा रहा है। “मुख्यमंत्री कन्यादान एवं निकाह योजना” में अब तक सवा दो लाख कन्याओं का विवाह हुआ है। राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में बेटियों की शिक्षा में प्रदेश की पहल को अन्य राज्यों के लिए मार्गदर्शी बताया गया है। महिलाओं की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक जनवरी से पूरे राज्य में महिला हेल्प लाईन शुरू की गई है। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रत्येक जिले में पृथक से अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में दोषसिद्ध अपराधियों के शस्त्र लायसेंस निरस्त किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत 14 लाख से अधिक मजदूरों के पंजीकरण, उनके हित में कोष संचय तथा मजदूरों को लाभ पहुचोने में किये गये व्यय के क्षेत्रों में देश में मध्यप्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है।

प्रदेश में हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल नि:शुल्क औषधि वितरण योजना शुरू की गई है। इसके तहत सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों को मुफ्त में दवाईयां दी जा रही हैं।

प्रदेश में संस्कृति और साहित्य के संवर्धन, संरक्षण,विस्तार और विकास के लिए बहुआयामी कार्य किये जा रहे हैं। बौद्ध दर्शन, बौद्धविचार और अनुशासन के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं तथा एशियाई विचारों के परस्पर सम्बन्ध, विकास और विस्तार के अध्ययन

का केन्द्र बन सके, इसके दृष्टिगत सांची में बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है।

प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 16 खेल अकादमी स्थापित की गई हैं। खेल विभाग का बजट पिछले नौ वर्षों में 25 गुना कर दिया गया है। मध्यप्रदेश खेल प्राधिकरण का गठन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए 11045 ग्राम पंचायतों को 361 करोड़ रूपये की लागत से खेल मैदानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री खिलाड़ी कल्याण कोष की स्थापना की गई। राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि दुगनी की गई।

मध्यप्रदेश के लिये यह गर्व की बात है कि यहां सर्वधर्म समभाव, शांति, एकता और सौहाद्र् की परम्परा हमेशा अक्षुण्ण रही है। हर परिस्थिति और हर हाल में यहां के विवेकशील और शांतिप्रिय नागरिकों ने एकता और भाईचारे को हमेशा कायम रखा है, जिसके लिये वे बधाई और सराहना के पात्र हैं।

मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की एक बात पुन: शुभकामनाएं देते हुए आह्वान करता हूं कि हम सभी एकजुट होकर मध्यप्रदेश और देश की प्रगति और विकास में सक्रिय रूप से सहभागी बनें और प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर उठाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान करें।

जय हिन्द, जय मध्यप्रदेश।